



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १४]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर २२, १९८५/अग्रहायण १, १९०७

No. 14]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 1985/AGRAHAYANA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, २२ नवम्बर, १९८५

का. नि. आ. १७ (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, रक्षा मंत्रालय में सम्मिलित पदा पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

नियम

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (नियम) १९८५ है।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषा :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) “कर्तव्य पद” से अनुसूची १ में सम्मिलित कोई स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है ;

(ग) “परीक्षा” से सेवा में, और ऐसी अन्य सेवा या सेवाओं में जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिविष्ट की जाएं, भर्ती के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित, प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा है, अभिप्रेत है ;

(घ) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ङ.) “श्रेणी” से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में “नियमित सेवा” से, उप श्रेणी में वीर्य अधि नियुक्ति के लिए, विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात् श्रेणी में की गई सेवा को अधि या अधि-धियां अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अधि या अधि-धियां भी हैं, —

(i) जो सेवा के आरम्भिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाती है।

(ii) जिसके या जिनके दौरान कोई अधिकारी श्रेणी में कर्तव्य पद धारण करता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा अनुपलब्ध न होता।

- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ज) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के बड़ी अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में हैं ; और
- (झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) अभिप्रेत है ।

3 भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) का गठन :—"भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क)" के नाम से एक ऐसा ही गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे । सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह "क" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ।

4. श्रेणियाँ, प्राधिकृत पद-संख्या और उच्चता पुनर्विलोकन :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

- (2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या बढ़ होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।
- (3) सरकार, कर्तव्य पदों की संख्या में ऐसी अस्थायी वृद्धियाँ या कमी कर सकेगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।
- (4) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अवर्जित कर सकेगी ।
- (5) सरकार, आयोग के परामर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया जाता है, सेवा की उपयुक्त श्रेणी में अस्थायी हैमियन या अधिष्ठात्री हैसियत में, जैसा ठीक समझा जाए, नियुक्त कर सकेगी और सव्य श्रेणी में उसकी निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

5. सेवा के सदस्य :— (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ के समय नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से ;
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति, उस तारीख से जिस तारीख को वे इस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं ;
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ पर, तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।
- (3) इन नियमों के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, तत्स्थानी श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

6 सेवा का प्रारम्भिक गठन :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को पूर्ववर्ती सैनिक भूमि और छावना सेवा (समूह क) के सब अधिकारी उन पदों या श्रेणियों के, जिन्हें वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व नियमित आधार पर धारण कर रहे थे सेवा में तत्स्थानी पदों पर या श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

टिप्पण :—सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति के पूर्व उपनियम (1) में उल्लिखित तत्स्थानी श्रेणी में की गई नियमित निर्धार सेवा को ज्येष्ठता प्रोन्नति, पृथक् और वेतन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(2) तत्पश्चात्, सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति द्वारा बरती के लिए आश्रित रिक्तियों के लिए संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार, इन नियमों के प्रकाशित होने से पूर्व, उन रिक्तियों के लिए जो कि किसी वर्ष विशेष में हुई हों, वर्षवार वेतन बनाएंगी ।

(3) उस सीमा तक जिस तक कि सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित पद-संख्या प्रारम्भिक गठन के समय इस नियम के उपनियम (1) और (2) के अनुसार बरी नहीं जाती है, नियम 7 के अनुसार बरी जाएगी ।

7. सेवा का प्रविष्टि में अनुक्षण :— (1) नियम 8 के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करके सेवा का प्रारम्भिक गठन पूर्ण हो जाने के पश्चात् रिक्तियाँ उस रीति से भरी जाएंगी जो इसमें इसके पश्चात् उपबोधित है ।

(2) (1) समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान में अधिष्ठात्री रिक्तियों का 75% आयोग द्वारा अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट लैङ्गिक अनुपातों और अनु सोना तथा परिक्षा की उस स्कीम के अनुसार जो कन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित की जाए, ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।

(ii) कनिष्ठ वेतनमान में शेष 25% अधिष्ठात्री और सभी अस्थायी रिक्तियों को योग्यता के अनुसार चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन व्यक्तियों की जो उस श्रेणी के वेतन में सम्मिलित हैं वेतन में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में नियुक्ति द्वारा सिवाय तब के भरा जाएगा जबकि कोई व्यक्ति उसकी बारी जाने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है ।

(3) उपनियम (2) (ii) में निर्दिष्ट वेतन, ऐसे छावनी कार्यालयक अधिकारी (समूह ख) और सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी (समूह ख) में से, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है, 1 : 1 के अनुपात से योग्यता के अनुसार चयन के आधार पर भरा किया जाएगा ।

(4) सेवा के समूह क उच्च वेतनमान और उपर के वर्गों पर नियुक्तियाँ अपनी विस्तार श्रेणियों में से ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा की जाएगी जिन्होंने अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है जिसके प होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा की जाएगी । प्रतिनियुक्ति पर भर्ती यदि आवश्यक हुई तो, सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करने के बाद की जाएगी ।

(5) प्रोन्नतियों के लिए अधिकारियों का चयन, अनुसूची 4 में दक्षित संरचना के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर योग्यता के अनुसार चयन द्वारा किया जाएगा (जिन्हे समूह क ज्येष्ठ वेतनमान तथा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) चयन श्रेणी (के पदों पर, प्रोन्नति अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करने हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी) ।

8 परीक्षा (1) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त, व्यक्ति चाहे वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं या प्रोन्नति द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे

परन्तु सरकार परीक्षा के दौरान असंतोषप्रद कार्य संपादन के कारण या विभागीय परीक्षा में असफल होने या किसी अन्य कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी व्यक्ति की परीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है ।

परन्तु यह और कि परीक्षा की अवधि बढ़ाने को बाबत विभिन्न प्राथमिक परीक्षा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सामान्यतया 6 से 8 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सम्बद्ध व्यक्ति को उसके कारणों अहित स्मृति किया जाएगा ।

(2) परीक्षा की अवधि पूर्ण होने पर, व्यक्तियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो, यथास्थिति, उनको नियुक्ति में पुष्ट किया जाएगा या उन्हें उनकी नियुक्ति में नियमित आधार पर रखा जाएगा और उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्तियों में सम्बन्ध अनुक्रम में उनकी पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, उपनिबन्ध (1) में विनिर्दिष्ट परीक्षा की अवधि या उनकी नगई गई अवधि के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अवधारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है या यदि, ऐसी परीक्षा की अवधि या उसकी नगई गई अवधि के दौरान, सरकार का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्तियों ऐसी परीक्षा की अवधि या उसकी नगई गई अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा तो सरकार, ऐसे कारणों में जा लेखबद्ध करेगा, अवधारी को या तो सेवाभूक्त कर सकती है या सेवा के समुह के कनिष्ठ वेतनमान में, जिसे वह प्रोत्ति होने से पूर्व धारण कर रहा था, उसके अधिष्ठायी पर बर प्रतिबन्धित कर सकती है या ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह ठीक समझे ।

(4) परीक्षा की अवधि के दौरान, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों से परीक्षा की सर्वाधिकतम रूप से पूर्ण करने की एक शर्त के रूप में, केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षाएँ और परीक्षण (जिसके अन्तर्गत द्वितीय परीक्षा और लाभ बहादुर पारसक, पदवीय प्रशासन अध्यादेशों के कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण भी है) देने की अपेक्षा कर सकती जो वह ठीक समझे :

परन्तु यदि कोई परीक्षाधीन व्यक्ति ऐसी परीक्षा उत्तायी नहीं कर पाया उसकी वह पहली वेतनवृद्धि, जिसे वह परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् पाने का हकदार हो जाता है, एक वर्ष के लिए या उस तारीख तक के लिए जिसका वह आगामी वेतनवृद्धि का हकदार हो जाता है, शर्त में से जा की पूर्ववर्ती है, प्रसन्नता पधान में मुन्नगी कर दी जाएगी ।

9. सेवा के सदस्यों की सेवा में नियुक्ति, सेनाधी और स्थानान्तरण.— सेवा में सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाएँगी और सेवा के सदस्यों की सेनाधिया और उनका स्थानान्तरण महाविदेशक, रक्षा सपदा द्वारा किए जाएँगे ।

10. भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर सेवा करने का अधिकार और सेवा की शर्तें :

- (1) सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी भारत में कहीं भी या भारत से बाहर सेवा करने के दायी होंगे ।
- (2) प्रतिनियुक्त किए जाने पर अधिकारी, भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या भारत सरकार के अधीन किसी निगम या औद्योगिक उपक्रम में सेवा करने के दायी होंगे ।
- (3) सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें, उन मामलों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में उपबंध नहीं किए गए हैं, वैसी ही होंगी जो साधारणतः केन्द्रीय विधिल सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती है ।

11. निरुद्धताएँ :— वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमोदित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

12. विधि न करने की शक्ति :— जहाँ सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह यह, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के कितने उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, सिधिल कर सकती है ।

13. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आदेशों, आधु सीमा में छूट और अन्य विधायकों पर प्रभावशाली आयेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुमोदित जातियों, अनुमोदित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

14. निर्वेचन :— यदि इन नियमों के निर्वेचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

15. निरसन :— सैनिक भूमि और छावनी सेवा (समूह क) नियम 1981 निरसित किए जाते हैं :—

परन्तु ऐसा निरसन ऐसे निरसन से पहले उक्त नियमों के अधीन की गई या करने से भोग की गई किसी बात या कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

अनुसूची 1]

[नियम 3 का खण्ड (ख) और नियम 4 का उपनिबन्ध (1) देखिए]

भारतीय रक्षा सपदा सेवा (समूह क) की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित सर्वोच्च पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1. महाविदेशक		1	2750 रु. नियत
2. उपर महाविदेशक/निदेशक (स्तर-I)		4	2500-125/2-2750 रु.
3. उप महाविदेशक/निदेशक (स्तर-II)		6	2250-125/2-2500 रु.

1	2	3	4
4. संयुक्त निदेशक (चयन ग्रेड)	3	2000-135/2-2250 रु.	
5. संयुक्त निदेशक (साधारण ग्रेड)/सहायक महानिदेशक	14	1500-60-1800-100-1000 रु.	
6. सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छायनी कार्यपालक अधिकारी (व्यप्ट वतनमान)	56	1100 (6ठा वर्ष या कम) 50-1600 रु. अनुसूची 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए	
7. छावनी कार्यपालक अधिकारी/सम्बन्ध अधिकारी (कनिष्ठ वतनमान)	32	700-40-900-द.री - 10-1, 10-50-1300 रु.	

अनुसूची-2

[नियम 7 का उप नियम (2) देखिए]

संयुक्त सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) के समूह का कनिष्ठ वतनमान पर सीधे भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु-सीमा।

(1) अभ्यर्थी के पास भारत के केन्द्रीय या किसी राज्य विद्यालय मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित, किसी अन्य शिक्षा संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1953 को धारा 3 के अन्तर्गत घोषित किए समस्त गए विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्वयन पर अनुसूचि निदेशों विरुद्ध विदेशों में को उपाधि या ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई है।

(2) जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो किन्तु 28 वर्ष की आयु का न हुआ हो। 1935 तथा इसके बाद आयोजित परीक्षा के लिए ऊपर की आयु सीमा 26 वर्ष होगी।

अनुसूची 3

[नियम 7 का उपनियम (1) (3) और (4) देखिए]

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर भर्ती के पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक निम्नतर श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4
1. महानिदेशक (2750 रु. निपन)	प्रोन्नति द्वारा		ऐसे ऊपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-I) जो नियमित आधार पर नियुक्त हो।
2. अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-I) (2500-2750 रु.)	-वही-		ऐसे उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-II) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्त श्रेणियों में 2 वर्ष सेवा की है।
3. उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-II) (2250-2500 रु.)	-वही-		ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक जिन्होंने उम्र श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। इसके न होने पर ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक जिन्होंने 10 वर्ष संयुक्त नियमित सेवा निम्नलिखित श्रेणियों में की है— संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/उप निदेशक और सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छायनी कार्यपालक अधिकारी (व्यप्ट वतनमान)
4. संयुक्त निदेशक (चयन ग्रेड) (2000-2250 रु.)	अचयन आधार पर		ऐसे संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक जिन्का वतनमान अधिकतम सीमा तक अर्थात् 2000 रु. तक, पहुँच चुका हो तथा 2 वर्ष से बड़ी पर रखा है।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य ग्रेड)/सहायक महानिदेशक (1500-2000 रु.)	प्रोन्नति द्वारा		ऐसे सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छायनी कार्यपालक अधिकारी (व्यप्ट वतनमान) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। इनके न मिलने पर ऐसे सहायक निदेशक/उप सहायक महानिदेशक

1	2	3	4
			रक्षा, सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने 9 वर्षों में संयुक्त नियमित सेवा 15 श्रेणी में की है।
			महायुक्त निदेशक/उप महायुक्त महानिदेशक/रक्षा सम्पदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) तथा छावनी कार्यपालक अधिकारी/सम्पदा अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)
6. सहायक निदेशक/उपसहायक महानिदेशक/रक्षा सम्पदा प्रोन्नति द्वारा (अवयव आधार अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ वेतनमान) पर (1100-1600 रु.)			ऐसे छावनी कार्यपालक (अधिकारी), सम्पदा अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) जिन्होंने परिवर्षा अवधि मरुतापूर्वक पूरी कर ली है विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा उस श्रेणी में 1 वर्ष की नियमित सेवा की है।
7. छावनी कार्यपालक (अधिकारी) सम्पदा अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान) (700-1300 रु.)	(1) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा छावनी कार्यपालक अधिकारी सेवा (समूह ख) और रक्षा सम्पदा अधिकारी सेवा (समूह ख) के ऐसे अधिकारियों में से (2) 75 प्रतिशत नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार सेवाओं द्वारा		1.1 अनुपात में जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

मार्ष्टीकरण

- (1) कनिष्ठ श्रेणी : निदेशक (साधारण श्रेणी), महायुक्त महानिदेशक की प्रोन्नति की पात्रता के निर्धारण के लिए तत्कालीन 400-409-150-30-510-द.रो.-70-40-1100-50-12-1250 रु. के वेतनमान में 1-1-1973 में पहले उस श्रेणी में दक्षलक्ष्य पार करने के बाद की गई सेवा 1100-1600 रु. (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड में की गई सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
- (2) ऊपर क्रम सं. 1 में दिए गए पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण के लिए तत्कालीन 2000-2500 रु. की श्रेणी में की गई सेवा 2250-2500 रु. (स्तर-II) की श्रेणी में की गई सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

अनुसूची-4

[नियम 7 का उप नियम (5) देखिए]

भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा (समूह क) के समूह क पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :-

क.स.	पदनाम	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) पद क विभागीय प्रोन्नति समिति
1	2	3	4
1. महानिदेशक		(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. अ. योग--अध्यक्ष (2) सचिव/अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--सदस्य	(1) सचिव, रक्षा मंत्रालय--अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--सदस्य
2. अपर महानिदेशक/निदेशक (स्तर-1)		(1) अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आ. अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा--सदस्य	(1) सचिव, रक्षा मंत्रालय--अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--परक्ष (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा--परक्ष
3. उप महानिदेशक/निदेशक (स्तर-2)		(1) अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. आ.--अध्यक्ष (2) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा--सदस्य	(1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय--अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा--परक्ष (3) मुख्य सचिव (पे एंड डायरी) रक्षा मंत्रालय--सदस्य
4. संयुक्त निदेशक (गैर-कार्यात्मक) (चयन श्रेणी)		(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डायरी), रक्षा मंत्रालय--अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा--सदस्य (3) अपर महानिदेशक, रक्षा संपदा--सदस्य	

1	2	3	4
5. संयुक्त निदेशक (साधारण श्रेणी)/ सहायक महानिदेशक	(1) अध्यक्ष/सदस्य, स. मा. से. आ.—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय— सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय— अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	
6. सहायक निदेशक/उप सहायक महा- निदेशक/रक्षा संपदा अधिकारी/छावनी कार्यपालक अधिकारी (दरिष्ठ वेतन- मान)	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय— अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य (3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय— अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य (3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य	
7. छावनी कार्यपालक अधिकारी/संयुक्त अधिकारी (कनिष्ठ वेतनमान)	(1) अध्यक्ष/सदस्य, स. मा. से. आ.—अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय— सदस्य (3) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य	(1) संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय— अध्यक्ष (2) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य (3) उप सचिव (सी पी) रक्षा मंत्रालय—सदस्य	

टिप्पण: 1. यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उनके अधिनियम में उल्लिखित रहे हैं तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से निम्न कितने सदस्यों के अनु-
पस्थित रहने से समिति को कार्यवाई अविधिमत्त्व नहीं होगी।

टिप्पण: 2. पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोत्ति समिति को कार्यवाई आयोग के अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं
करता है तो विभागीय प्रोत्ति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में तुरंत से होगी।

टिप्पण: 3. यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी को मरने पर उच्चतर पद में प्रोत्ति के प्रयाजन के लिए विचार दिया जाता है तो
श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के मामलों पर भी, इस बात को विचार में लाए बिना कि उन्होंने अपेक्षित सभी तरह सेवा नहीं की है
विचार दिया जायेगा।

संशोधन आयोग

सैनिक भूमि और छावनी सेवा समूह 'क' के लिए शर्ती नियम का. नि. आ. स. 23(अ), तारीख 23-10-81 के अंगत सन् 1981 में सब लोक
सेवा आयोग के परामर्श से (देखिए उनके पत्र स. एफ. 3/4(13)/77/आर.आर. तारीख 23-4-1981) प्रकाशित किए गए थे।

उपर्युक्त नियम छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अंगत बनाए गए थे। उपर्युक्त अधिनियम का छावनी
(संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन किया गया है और ऊपर उल्लिखित खंड का लोप किया गया है। इस प्रकार नियम के मगाध करने के लिए कोई
समर्थकारी खंड नहीं है। सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से ऊपर के पदों के वेतनमान का ऊपर की ओर पुनरावलोकन किया गया था और सरकार
के पत्र स. एफ. 15(2)/79-डी (न्यू एंड सी), तारीख 29 जुलाई, 1983 द्वारा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में स्तर 1 और 2 सुचित किए गए थे। उता पत्र द्वारा अरर
महानिदेशक के पद का मूजन किया गया था और संयुक्त निदेशक के पद अकुत्कारों के पद हो गए और उता सब 5 में 3 हो गई। कुछ और मां लक्ष
सैनिक भूमि और चयन (समूह क) नियम, 1981 के लागू करने में वैया हो गए, विशेष रूप से उनके नियम 6 में सम्मिलित किए गए परिणाधिक गठन खंड
की बाबत जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियां जमा हो गई और वहां सदा में अतिरिक्त अनुष्ठान श्रमते सेवा के अधिकारियों पर कुपभाव पड़ने की समाधान है। इस
बीच में सरकार ने सेवा के नाम को भारतीय रक्षा संपदा सेवा (समूह क) का नाम देने का विनिश्चय किया।

तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्कु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए शर्ती नियम बनाने की प्रस्थापना है जिससे कि उपर्युक्त
कठिनाइयां और कमियों का समाधान हो सके तथा विशेष रूप से उन रिक्तियों को वितरित किया जा सके जो विभिन्न श्रेणियों में पिछले दिनों में हुई है और
चयन सूची तैयार करने के लिए इन नियमों के लागू करने का तत्परा का विधान है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक शर्ती नियमों को प्रकाशित करने से सेवा में विद्यमान कितने व्यक्ति पर कोई नोहान सारा नहीं पड़ेगा।

[क. सं. 103/57/प.पी.एम/ए.ए.सी.]

क. आ. निवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd November, 1985

S.R.O. 17 (E) :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment (and conditions of service of persons appointed) to the posts included in the India Defence Estates Service, Ministry of Defence, namely :—

RULES

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Indian Defence Estates Service (Group A) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition :—In these rules unless context otherwise requires,

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;
- (c) "Examination" means a combined competitive examination consisting of a preliminary examination and a main examination conducted by the Commission for recruitment to the Service and such other Service or Services as may be specified by the Government from time to time;
- (d) "Government" means the Central Government;
- (e) "Grade" means a grade of the Service;
- (f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade rendered after selection, according to prescribed procedure, for a long term appointment to that grade and includes any period or periods,—
 - (i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;
 - (ii) During which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (g) "Schedule" means a Schedule to these rules;
- (h) "Schedule Castes" and "Schedule Tribes" shall respectively have the same meaning as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution; and

(i) "Service" means the Indian Defence Estates Service (Group A) constituted under rule 3.

3. Constitution of the Indian Defence Estates Service (Group A) :—There shall be constituted a Service known as "Indian Defence Estates Service (Group A)" consisting of persons appointed to the service under rules 6 and 7. All the posts included in the Service shall be classified as Group A posts.

4. Grades, authorised strength and its review :—
(1) The duty posts included in the various grades of the Service, their number and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary additions to or deletions from the strength of the duty posts in various grades as it may deem necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule I or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account his continuous regular service in the analogous grade.

5. Members of the Service :—(1) The following persons shall be members of the Service, namely :—

- (a) persons appointed to the Service at the commencement of these rules under rule 6, from the date of such commencement;
- (b) persons appointed to the Service after the commencement of these rules, from the date they are so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such commencement, be deemed to be a member of the Service in the corresponding grade.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service :—

(1) All officers in the erstwhile Military Land and Cantonments Service (Group 'A') on the date of

commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the Service in the posts or grades corresponding to those which they were holding on regular basis before such commencement.

Note : The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) in the respective corresponding grade prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of qualifying service for seniority, confirmation, promotion and pension.

(2) Thereafter, for the vacancies intended to be filled by promotion, in various grades of the Service, the Departmental Promotion Committee concerned shall prepare year-wise panels, for the vacancies which arose in a particular year before publication of these rules, as per the Government instructions on the subject.

(3) To the extent the authorised strength of various grades in the Service is not filled at the time of initial constitution, as in sub-rules (1) and (2) of this rule, it shall be filled in accordance with Rule 7.

7. Future maintenance of the Service :—

(1) After the initial constitution of the Service has been completed by the appointment of officers in accordance with rule 6, vacancies shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) (i) 75 per cent of the substantive vacancies in Group 'A' Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a competitive examination conducted by the Commission in accordance with the educational qualifications and age limit as specified in Schedule II and the Scheme of examination as may be notified by the Government, in consultation with the Commission, from time to time.

(ii) The remaining 25 per cent substantive and all temporary vacancies in the Junior Scale shall be filled by appointment of persons by promotion on the basis of selection on merit included in the panel for this grade in the order of seniority in the panel except when for reasons to be considered in writing if a person is not considered fit for such appointment in his turn on the recommendations of the DPC.

(3) The panel referred to in sub-rule (2) (ii) shall be prepared on the basis of selection on merit in the ratio of 1 : 1 from amongst such cantonment Executive Officers (Group B) and the Assistant Defence Estates Officers (Group B) as have rendered not less than 3 year's regular service in the respective Grades.

(4) Appointment to the posts in Group A senior scale and above of the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grades with the minimum qualifying service as specified in Schedule III, failing by which transfer on deputation.

Recruitment by transfer on deputation shall, if necessary, be made by the Government after consultation with the Commission.

(5) The selection of officers for promotion shall be made by selection on merit (except in the cases of promotion to the posts in Group A Senior Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade) which shall be in the order of seniority subject to rejection of the unfit) on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the composition given in Schedule IV.

8. Probation :—(1) Every person on appointment to the junior scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion to that scale, shall be on probation for two years :

Provided that the Government may extend the period of probation of any person for unsatisfactory performance during the probation or for failure to pass the departmental examination or for non-completion of training or for any other reasons to be recorded in writing :

Provided further that the decision regarding extension of period of probation shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation ordinarily within a period of 6 to 8 weeks and communicated to the concerned person together with the reasons for such extension.

(2) On the completion of the period of probation, persons shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in their appointment or be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that a candidate is not fit for permanent appointment or if, at any time during such period of probation or extension thereof, the Government is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation or extension thereof, the Government may, for reasons to be recorded in writing, discharge or revert the candidate to the post which he has been holding before his promotion to the Junior Scale of Gr. 'A' of the Service as the case may be or pass such orders as it deemed fit.

(4) During the period of probation, candidates appointed by direct recruitment may be required by the Government to undergo such course of training & instructions and examination and tests (including test in Hindi and the test at the end of the course at Lal

Bahadur Shastri National Academy of Administration) as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation :

Provided that in case any of the probationers do not pass such test, the first increment which he would be entitled to draw after the result of the test are announced, shall be postponed non-cumulatively by one year upto the date on which he becomes entitled to the next subsequent increment, whichever is earlier.

9. Appointment to the Service, posting and transfer of Members of the Service.—All appointments to the Service shall be made by the President and the postings and transfers of the members of the Service shall be made by the Director General, Defence Estates.

10. Liability to serve in any part of India or outside and other conditions of service.—(1) Officer is appointed to the service shall be liable to serve any where in India and/or outside.

(2) Officers, if deputed, shall be liable to serve in, any other Ministry or Department of the Government of India or Corporation and Industrial Undertaking under the Government of India.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provisions is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to officers of Control Civil Services, in general.

11. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order or reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

14. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

15. Repeal.—The Military Land and Cantonments Service (Group A) Rules, 1981 are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken or omitted to be done or taken under the said rules, before such repeal.

SCHEDULE-I

[See Clause (b) of rule 2 and sub-rule (1) of rule (4)]

Name, number and scale of pay of Duty Posts included in the various Grade of the Indian Defence Estates Service (Group A)

S. No.	Name of the Post	No. of Posts	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General	1	Rs. 2750 fixed.
2.	Additional Director General/Director (Level I)	4	Rs. 2500-125/2-2750
3.	Deputy Director General/Director (Level II)	6	Rs. 2250-125/2-2500
4.	Joint Director (Selection Grade)	3	Rs. 2000-125/2-2250.
5.	Joint Director (Ordinary Grade)/ Assistant Director General.	14	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
6.	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estates Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale).	56	Rs. 1100 (6th year or under)-50-1 600 subject to provisions of Schedule III.
7.	Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale).	32	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

SCHEDULE-II

[See sub-rule (2) of rule 7]

Minimum educational qualifications and age limit for direct recruitment to posts in Group A Junior Scale of the Indian Defence Estates Service (Group A) for the competitive examinations to be conducted by the Union Public Service Commission

A candidate must have :—

- (1) A Degree of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislation in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1958 or a foreign University approved by the Government from time to time or possess qualification which has been recognised by the Government for the purpose of admission to the examination.
- (2) Attained the age of 21 years but must have not attained the age of 28 years on the first day of January in which the examination is held. The upper age limit shall be 26 years for the examination to be held in 1985 and thereafter.

SCHEDULE-III

[See sub-rule (2), (3) and (4) of rule 7]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Defence Estates Service (Group A)

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment	Field of selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General (Rs. 2750 fixed)	By promotion	Additional Director General/Director (Level I) appointed on regular basis.
2.	Additional Director General/Director (Level I) (Rs. 2500-2750)	-do-	Deputy Director General/Director (Level II) with 2 years service in the grade rendered his appointment thereto on a regular basis.
3.	Deputy Director General/Director (Level II) (Rs. 2250-2500)	By promotion	Joint Director/Assistant Director General, Deputy Director with 7 years regular service in the grade filling which Joint Director/Assistant Director General/Deputy Director with 10 years combined regular service in the grades of Joint Director/Assistant Director General/Deputy Director and Assistant Director, Deputy Assistant Director General/Defence Estates Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale).
4.	Joint Director (Selection Grade) (Rs. 2000-2250)	By promotion on non-selection basis	Joint Director/Assistant Director General who have secured the maximum of pay scale, i.e. Rs. 2000/- and have stayed in for not less than 2 years.
5.	Joint Director (Ordinary Grade)/Assistant Director General (Rs. 1500-2000)	By promotion	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estates Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) with 5 years regular service in the grade, filling which Assistant Director/

(1)	(2)	(3)	(4)
			Deputy Assistant Director General/Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) with 9 years combine regular service in the grades of Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) and Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale).
6	Assistant Director/Deputy Assistant Director General/Defence Estate Officer/Cantonment Executive Officer (Senior Scale) (Rs. 1100-1600)	By promotion (on non-selective basis)	Cantonment Executive Officer/Attached Officer (Junior Scale), who have successfully completed the probation, including passing of departmental examination and have rendered 4 years service in the grade on regular basis.
7	Cantonment Executive Officer/Attached Officers (Junior Scale) (Rs. 700-1300)	(i) 25% by promotion. (ii) 75% by direct recruitment in accordance with sub-rule (2) of rule 7.	From amongst the officers of the Cantonment Executive Officers Service (Group B) and Defence Estate Officers Service (Group B) in the ratio of 1 : 1 with 3 years regular service in their respective grades.

Explanation :—

- (1) For determining the eligibility for promotion to posts of Joint Director (Ordinary grade)/Assistant Director General, service rendered in the erstwhile pay scale of Rs. 400-400-450-30-510-EB-70-40-1100-50/2-1250 prior to 1-1-1973, after crossing of efficiency Bar therein shall be counted as service rendered in the grade of Rs. 1100-1600 (Senior Scale).
- (2) For determining the eligibility for promotion to the posts at St. No.2, service rendered in the erstwhile grade of Rs 2000-2500 shall be counted as service in the grade of Rs 2250-2500 (Level II).

SCHEDULE IV

[See sub-rule (5) of rule 7]

Composition of Group A Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation to Group A posts in the Indian Defence Estates Service (Group A).

S No.	Name of the post	Group A D.P.C. (for considering promotion)	Group A D.P.C. (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary, Ministry of Defence —Member	(i) Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Additional Secretary Ministry of Defence —Member
2.	Additional Director General/ Director (Level-I)	(i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence —Member	(i) Secretary, Ministry of Defence —Chairman (ii) Additional Secretary, Ministry of Defence —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) Director General, Defence Estates	—Member	(iii) Director General, Defence Estates — Member
3. Deputy Director General/ Director (Level II)		(i) Chairman/Member, UPSC	—Chairman	(i) Additional Secretary, Ministry of Defence — Chairman
		(ii) Additional Secretary, Ministry of Defence	—Member	(ii) Director General, Defence Estates — Member
		(iii) Director General, Defence Estates	—Member	(iii) Joint Secretary (P & W), Ministry of Defence — Member
4. Joint Director-Non-functional Selection Grade)		(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence.	—Chairman	
		(ii) Director General, Defence Estates	—Member	
		(iii) Additional Director General, Defence Estates	—Member	
5. Joint Director, (Ordinary Grade)/Assistant Director General		(i) Chairman/Member, UPSC	—Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman
		(ii) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence	—Member	(ii) Director General, Defence Estates — Member
		(iii) Director General, Defence Estates	—Member	
6. Assistant Director/Deputy Assistant Director General/ Defence Estates Officer/ Cantonment Executive Officer (Senior Scale)		(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence.	—Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman
		(ii) Director General, Defence Estates	—Member	(ii) Director General, Defence Estates —Member
		(iii) Deputy Secretary (CP), Ministry of Defence	—Member	(iii) Deputy Secretary, Ministry of Defence — Member
7. Cantonment Executive Officer/ Attached Officer (Junior Scale)		(i) Chairman/Member, UPSC	—Chairman	(i) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence — Chairman
		(ii) Joint Secretary (P&W), Ministry of Defence	—Member	(ii) Director General, Defence Estates —Member
		(iii) Director General, Defence Estates.	—Member	(iii) Deputy Secretary (CP), Ministry of Defence —Member

Note 1 : The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not be invalidate the proceeding of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attend its meetings.

Note 2 : The proceeding of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Note 3 : If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher posts, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Recruitment Rules for Military Lands and Cantonment Service Group 'A' were published vide SRO No. 23(E) dated 23-9-1981 in 1981 in consultation with the Union Public Service Commission vide their letter No. F. 3/4 (13)/77-RR dated 23-4-1981.

The above Rules were framed under Clause (cc) Sub-section (2) of Section 240 of the Cantonments Act 1924. The aforesaid Act has been amended by Cantonment (Amendment) Act 1983 and the aforesaid Clause has been omitted thus leaving no enabling Clause for amendment of the Rules. Besides, as a result of a review, upward revision of scales of pay of the posts above the Junior Administrative Grade in service was sanctioned and levels I and II created in Senior Administrative Grade, by the Government vide letter No. F.15(2)/79/D(Q&C) dated 29th July, 1983. Under the same letter the post of Addl. D.G. was created and the posts of Jt. Director became non-functional stagnation posts, the number of which was reduced to 3 from 5. Certain complications also arose in the application of Military Lands and Cantonment (Group 'A') Rules, 1981, especially the initial constitution Clause incorporated in rule 6 thereof which resulted in bunching of vacancies and consequent large scale supersessions which are likely to demoralise the officers of the Service. In the meanwhile, Government have also decided to change the name of the Service to Indian Defence Estates Service (Group 'A').

Accordingly, it is proposed to frame fresh Recruitment Rules in exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution to overcome the above difficulties and lacunae providing in particular, for the splitting of vacancies which arose in the past in the various grades and exist on the date of promulgation of the Rules, yearwise, for preparing the select list.

It is certified that the publication of the proposed Recruitment Rules would not adversely affect any person presently in service.

[F. No. 103/57/ADM/L & C]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.